ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

अशुद्ध जल से हाथ धोना न धोना बराबर

रविवारीय, 22 - 28 मार्च 2020 वर्ष- एक, अंक-33, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेंट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

जनता कर्फ्यू को मिला पूरा समर्थन

झारखंड हुआ लॉकडाउन

कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुये झारखंड में इसके प्रसार को रोकने के लिये कड़े समाजिक अलगाव के उपायों को अपनाना उचित एवं आवश्यक समझते हुये झारखंड सरकार ने 31 मार्च तक पूर्णतया तालाबंदी की घोषणा की है। आकस्मिक सेवाओं को छोड़ कर राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। परंतु वे मुख्यालय का परिचालन नहीं करेंगे। परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता देखते हुये अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जायेगा। सभी कार्य के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी नागरिक अपन घर में ही रहेंगे। एवं बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

राशन दूकान, दवा दूकान, बैंक, एटीएम, पोस्टल सेवायें, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, दूध की सेवा, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशामन सेवायें चालू रहेंगी।

जाम का पर्याय रातू रोड का पिस्का मोड़ इलाका बिल्कुल सन्नाटा रहा

पिस्का मोड़ का मछली बाजार पूर्णतः बंद रहा

मुख्य संवाददाता

रांची : कोरोना के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने रविवार 22 मार्च को देशवासियों से जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। जिसमें लोगों को सुबह सात बजे से लेकर रात नौ बजे तक सबों को अपने घरों में रहने को कहा गया था। प्रधानमंत्री के इस आह्वान का पूरा असर जनता में देखा गया और रांची की सड़के बिल्कुल ही वीरान रही। यहां तक की गली मुहल्ले की दूकानें और प्रतिष्ठान भी बंद रहे। ग्रीन रिवोल्ट संवाददाता ने रांची के सबसे घने रिहायशी इलाकों में से एक रातू रोड का जायजा लिया और पाया कि रातू रोड तो पूरा सन्नाटा था ही कॉलोनियों और गलियों की छोटी दूकानें भी लोगों ने बंद रखी थीं। ये सब बगैर किसी दबाव के जनसहयोग वाला रहा। जिसमें जनता ने कोरोना के फैलने के चक्र को तोड़ने के लिये स्वतःफूर्त बंद रखा। किसी आपदा से लड़ने के लिये ऐसा देशव्यापी बंद और जनसमर्थन संभवतः पहली बार देखने को मिला है।

यात्री स्टेशन और बस स्टैंड में फंसे

रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डों तक में सन्नाटा पसरा रहा। बंद शुरू होने से पहले आ चुके ट्रेनों और बसों से आने वाले यात्री प्लेटफार्म और बस स्टैंड में फंस गये। उन्हें अपने घर तक जाने का कोई साधन नहीं मिल पाया। रांची और हटिया रेलवे स्टेशनों से इन यात्रियों को निकाल दिया गया तो ये स्टेशन के अहाते में बने शेड में मायूस होकर जनता कर्फ्यू के खत्म होने के बाद ही अपने घर जाने की उम्मीद में इंतजार करते दिखे।

महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति होने पर झारखंड बिहार से काम करने गये लोग वापस आने लगे और ऐसे लोग ही बंदी में फंस गये। ये यात्री अपने आप में एक खतरा हैं क्योंकि महानगरों में खतरे को देखते हुये ये अपने राज्य को भाग तो रहे हैं, पर इनमें से कुछेक भी संक्रमित होंगे तो ये महानगरों की इस महामारी को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे।

क्या कोरोना के दुष्चक्र को हम तोड़ पायेंगे?

सारे विश्व को तबाह कर रहे इस महामारी की मार हमारे देश पर भी पड़ी है। जानकारों का ये कहना कि जब इटली, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देश भी इससे निबट नहीं पा रहे और रोज दो चार सौ मौतें हो रही हैं ऐसे में भारत में अगर ये महामारी तीसरे चौथे चरण में पहुंची तो प्रलय सी स्थिति पैदा हो जायेगी। ये आशंका गलत भी नहीं है हमारे देश में **28000 लोगों पर एक डॉक्टर** है। हालात बिगड़ने पर अस्पतालों में बेड की कौन कहे अस्पताल, दवा और देख भाल करने वालों तक की कमी हो जायेगी? इटली में ऐसा दृश्य हम देख चुके हैं, वहां बुजुर्ग मरीजों को मरने के लिये छोड़ दिया गया। सारा विश्व हमें इसी आशंका में देख रहा है। **सावधानी और संकल्प से ही हम बचेंगे** : कोरोना को अगले चरण में जाने से रोक कर ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। और इसके लिये कम लोगों से मिलना, घर पर ज्यादा समय देना, बाहरी लोगों से संपर्क से बचना, लापरवाह होकर मजाक उड़ाना और यत्र तत्र जाने से बचना, संक्रमण का शक होने पर बगैर शर्म संकोच के अपनी जांच करवाना, किसी और के संक्रमित होने की आशंका पर पुलिस प्रसाशन को खबर करना, स्वच्छ सेनिटाइज रहना, यात्रा से बचना ही हमें कोरोना की मार से बचा सकता है। रोग से पहले बचाव की युक्ति ही फिलहाल इसकी काट है।

नहीं हो रही जांच

मुंबई, दिल्ली, पंजाब या अन्य जगहों से झारखंड आ रहे लोग राज्य के लिये बड़ा खतरा हैं। हटिया और रांची स्टेशनों पर जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच नहीं हो रही है। जबकि इन यात्रियों में ज्यादतर खुद कह रहे हैं कि यहां जांच होनी चाहिये थी ताकि हम संक्रमण के बारे में आश्वस्त हो सके। यदि हम संक्रमित हुये तो अपने घरों के बजाय पहले अस्पताल जायेंगे लेकिन यहां तो उसकी जांच ही नहीं हो रही है। यही हाल बस स्टैंड पर भी पहुंचे यात्रियों का भी है। राज्य सरकार ने यहां भयंकर लापरवाही दिखाई है।

विदेशों और खाड़ी से आने वालों से भयंकर खतरा

खबर प्राकशित होने तक झारखंड में एक भी कोरोना पोजीटिव व्यक्ति नहीं मिला है। लेकिन बिहार में एक शख्स की मौत कोरोना से हो गयी जो कतर से हाल ही में लौटा था। **गांव भी खतरे में हैं:** क्योंकि गांवों से बहुत सारे लोग खाड़ी के देशों में कमाने के लिये गये हुये हैं। ऐसे लोग वापस लौट रहे हैं तो अपने धार्मिक मान्यताओं के चलते जांच करवाने से परहेज कर रहे हैं, आइसोलेशन या अस्पताल जाने से मना कर रहे हैं। मिलने जुलने की प्रवृति के कारण परिजनों और गांव वालों के लिये संक्रमण का जरिया बन रहे हैं।

सभी ट्रेने 31 मार्च तक रद्द

रांची :कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के क्रम मे चलते हुए प्रयासों को जारी रखते हुए रेलवे मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है की भारतीय रेलवे की सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं रद्द रहेंगी जिसके अंतर्गत दिनांक 31-03-2020 के 24:00 बजे तक राँची रेल मण्डल की सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं रद्द रहेंगी ।

- राँची रेल मण्डल की सभी लम्बी दूरी वाली मेल / एक्सप्रेस तथा इंटरसिटी ट्रेने (प्रीमियम ट्रेने भी) एवं सभी पैसेंजर ट्रेने दिनांक 31-03-2020 के 24:00 बजे तक रद्द रहेंगी।
- ट्रेने जो अपने मूल स्टेशन से दिनांक 22-03-2020 के सुबह 04:00 बजे से पहले खुल चुकी है, वह ट्रेने अपनी यात्रा पूरी कर अपने गंतव्य स्टेशन तक जाएंगी ।
- माल गाड़ियों का परिचालन चालू रहेगा ।

टिकट जमा कर यात्री पैसे रिफंड करा लें

रेलवे प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि दिनांक 31.03.2020 के 12:00 बजे रात तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द रहेंगी ।अतः रांची रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर (यूटीएस काउंटर)दिनांक 31.03.2020 तक बंद रहेंगे । रिजर्व टिकटों के लिए कुछ रिजर्वेशन काउंटर खुले रहेंगे ।दिनांक 21.03.2020 से दिनांक 21.06.2020 (3 महीने) रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेनों के लिए अपनी यात्रा दिनांक से 3 महीने के भीतर रिफंड काउंटर से अपना टिकट जमा करके यात्री रिफंड ले सकते हैं 'अतः यात्रियों से अनुरोध है कि स्टेशनों में आकर रिजर्वेशन काउंटर पर अतिरिक्त भीड़ करने से बचें ।

ओरमांझी जू में बर्ड फ्लू की मार

दस पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी है

रांची संवाददाताः राज्य अभी कोरोना के भय से हलकान है इसी बीच झारखंड के लिये एक और बुरी खबर है कि, रांची के ओरमांझी जू में बर्ड फ्लू ने कहर ढा दिया है और इसस नौ पक्षियों की मौत हो गयी है। हालांकि कोरोना के शोर में बर्ड फ्लू के दस्तक पर लोगों का ध्यान कम जा रहा है, पर ये झारखंड के लिये दोहरी मार है। पहले ही कोरोना के भय से लोगों ने चिकेन का त्याग कर दिया है और पोल्ट्री किसानों ने कई जगहों पर अपने मुर्गियों को जंगलों में फेंक दिया दिया था। अब बर्ड फ्लू की दस्तक से इस उद्योग को दोहरे नुकसान की आशंका है। हालांकि चीड़ियाघर प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार नौ पक्षियों की मौत के बाद अब किसी अन्या पक्षी में इसका संक्रमण नहीं मिला है, लेकिन हर तरह की सावधानी बरती जा रही है।

अब कोई संक्रमण नहीं है, लेकिन पोल्ट्री किसानों और लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है : डी वेंकटेश्वरूलु (निदेशक)

बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी रांची जू के प्रधान निदेशक वेंकटेश्वरूलु ने ग्रीन रिवोल्ट को बताया कि पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखने पर हम सभी एक्शन में आ गये थे। कुछ पक्षियों के मरने के बाद हमने अन्य पक्षियों को अलग कर दिया था लेकिन संक्रमण से कुल दस पक्षियों की मौत हो गयी। हमने मरे हुये पक्षियों के सैंपल कोलकाता लैब भेजे थे वहां से शक होने पर सैंपल भोपाल स्थित लैब में भेजे गये। वहां से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी गयी जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 12 मार्च को रिपोर्ट मिलने के बाद हमने जू में अब पूरी सावधानी बरतनी शुरू कर दी है, पूरे एरिया को सेनिटाइज किया गया है। अब जू में किसी और पक्षी या जानवर में इसके कोई लक्षण नहीं हैं। लेकिन अगर यहां के कुछ पक्षियों को बर्ड फ्लू हुआ था तो संभव है झारखंड में और भी कहीं इसका संक्रमण हो। पोल्ट्री किसानों को जांच पड़ताल करवा कर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि वहां पक्षियों की तादाद बहुत ज्यादा रहती है और वहां इसके फैलने का चांस ज्यादा रहता है। केंद्र से एक टीम आयी थी और यहां के सविलि सर्जन के साथ दो दिन पहले इसके खतरों से निबटने और रोकथाम के लिये एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है।

अवैध खनन, अनुशासनहीनता घटना के प्रति जीरो टॉलरेंस : सीएमडी, सीसीएल

हेल्पलाइन नंबर 0651 2365288 पर सुरक्षा की नज़र

संवाददाता रांची

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक गोपाल सिंह ने सुरक्षा विभाग की समीक्षा की और आवश्यक दिशानिर्देश दिये। सुरक्षा विभाग द्वारा अवैध खनन एवं सुरक्षा संबंधी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) से सीएमडी, सीसीएल को अवगत कराया गया और इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई।

गोपाल सिंह ने समीक्षा बैठक में कहा कि अवैध खनन, अनुशासनहीनता आदि घटना के प्रति जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance For Theft of Coal) कंपनी अपनाना जारी रखेगी। कंपनी के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी अवैध गतिविधी में संलिप्त पाये जाएगें तो कंपनी नियमानुसार कार्रवाई करेगी। साथ ही सीएमडी ने कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपना दैनिक व्यवहार अच्छा रखे और मार-पीट से परहेज करें। उन्होंने सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक को निर्देश दिया की कोयला चोरी की रोकथाम पर अपने सुरक्षा बल तथा पुलिस की मदद प्राप्त करते हुए हर संभव कदम उठाए जाएँ। श्री सिंह ने बताया की कोयला देश की ऊर्जा का स्त्रोत है तथा उसकी चोरी रोकने के लिए सीसीएल प्रतिबद्ध है। उन्होंने झारखण्ड सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कंपनी को हर संभव मदद राज्य सरकार द्वारा मिलता आ रहा है और संबंधित जिले में उपायुक्त तथा वरीय पुलिस अधिकारी छापेमारी, अवैध खदानों को बंद करने आदि जैसे कार्यों में सहयोग प्राप्त होता है।

गोपाल सिंह ने मुख्यालय परिसर दरभंगा हाउस, रांची में तत्काल से दो (02) QUICK REACTION TEAM गठित करने का भी निर्देश दिया जो समय समय पर विभिन्न क्षेत्रो आदि में जा कर वहाँ की विधि व्यवस्था का आकलन करेगा तथा आवशक कार्यवाई करेगा।

ज्ञातव्य हो की सीसीएल सुरक्षा विभाग द्वारा 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 0651-2365288 पर सभी कमांड क्षेत्रों से जुड़ी हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखा जाता है। यह हेल्पलाइन नंबर अवैध उत्खन्न, चोरी, मार-पीट, खदान के अंदर हुई घटना, औद्योगिक संबंध में बाधा आदि उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम हरकत में आता है तथा पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स जैसी सह एजन्सि के सहयोग से विभिन्न कोयला माइन पर विधि व्यवस्था तथा नज़र बनाए रखता है। सीसीएल मुखयालय की हेल्पलाइन नंबर 0651-365288 पर सुरक्षा की नज़र से जुड़ी कोई भी सूचना, अवैध खनन, कोयला चोरी आदि विषय कोई भी व्यक्ति किसी भी समय दे सकता है तथा दी गयी खबर की पुष्टि होने पर उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी और सूचक का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

सफल खेती में पोटाश उर्वरक का उपयोग जरूरी

अजय कुमार

- **खेती में किसानों की अनदेखी से पोटाश के संचित भंडार में कमी**
- **दशकों पहले राज्य की भूमि में पोटाश की उपलब्धता समुचित थी**
- **शोध सर्वे में राज्य के औसतन 25 प्रतिशत भूमि में पोटाश की कमी पाई गई**
- **फसलों के विकास एवं उत्पादों की गुणवत्ता में पोटाश उपयोगी**
- **मौसम की मार से बचाव में पोटाश मददगार**
- **सब्जी फसलों की खेती में पोटाश की अधिक जरूरत**

दशकों पहले आम धारणा थी कि झारखण्ड की भूमि में पोटाश का पर्याप्त संचित भंडार मौजूद है. हाल में किये गये शोध सर्वे में मृदा वैज्ञानिकों ने प्रदेश की भूमि में पोटाश की उपलब्धता न्यून से मध्यम स्तर का पाया गया है. बीएयू के मृदा वैज्ञानिक डॉ राकेश कुमार ने इसे सफल खेती हेतु चिंताजनक विषय की बात कही है. सर्वे में झारखण्ड प्रदेश के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, लोहरदगा, सिमडेगा, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ एवं धनबाद जिलों के करीब 25 प्रतिशत भूमि में पोटाश की उर्वरता न्युन स्तर का पाया गया है .जबकि अन्य जिलों में औसतन करीब 50 प्रतिशत भूमि में पोटाश की उपलब्धता मध्यम स्तर का पाया गया है. राज्य के अधिकतर किसान विभिन्न फसलों की खेती में केवल नेत्रजनधारी एवं स्फूरधारी उर्वरकों का उपयोग करते है. उर्वरकों के इस असंतुलित प्रयोग से खेती योग्य भूमि में मौजूद पोटाश भंडार के दोहन से इसके स्तर में लगातार कमी हो रही है. विशेषकर सब्जी फसल वाले खेतों में पोटाश की कमी गंभीर समस्या बनती जा रही है.

डॉ राकेश बताते है कि वैज्ञानिक शोध में पोटाश की अच्छी उपलब्धता फसलों के विकास एवं गुणवत्ता के साथ - साथ नेत्रजन, स्फूर एवं जिंक धारी उर्वरकों की दक्षता को बढ़ाने में उपयोगी पाया गया है. मौसम की प्रतिकूल स्थिति जैसे सुखा, ओला, पाला तथा कीट व्याधि आदि से बचाव में भी पोटाश के उपयोग को लाभकारी पाया गया है.

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय पोटाश संस्थान परियोजना के अधीन खाद्यान एवं नगदी फसलों विशेषकर सब्जी फसलों में पोटाश उर्वरक के प्रभाव का किसानों के खेतो में किये गये प्रत्यक्षण के बेहतर परिणाम मिले है। परियोजना अन्वेषक डॉ राकेश बताते है कि शोध में पोटाश के उपयोग से खाद्यान फसलों की उपज में 15 प्रतिशत एवं सब्जी फसलों में करीब 30 प्रतिशत तक अधिक उपज मिली. टमाटर, हरी मटर, बंधा गोभी एवं फुलगोभी की खेती में नेत्रजनधारी एवं स्फूरधारी उर्वरकों की पूरी मात्रा एवं पोटाश उर्वरक को दो भागों में बाँटकर प्रयोग करने से अधिकतम पैदावार एवं लाभ पाया गया. पोटाश उर्वरक की आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा फसल में कल्ले निकलने के समय डाला गया. ओरमांझी एवं कांके प्रखंड के किसानों के खेत में किये गये इन प्रत्यक्षणों में बेहतर लाभ के लिए पोटाश की अनुशंषित मात्रा या इससे अधिक मात्रा को दो भागों में बाँटकर प्रयोग करने से परंपरागत खेती की अपेक्षा अधिकतम शुद्ध लाभ पाया गया.

ओरमांझी, कुच्चु एवं पिठोरिया के किसान बालक महतो, राजेश्वर महतो, मधु साहू एवं राम प्रवेश गोप बताते है कि पोटाश के उपयोग से उन्हें सब्जी फसल में एकसमान फसल पकवार, आकर्षक, स्वस्थ्य एवं आकार में बड़े सब्जी फसल प्राप्त हुआ. सब्जी की गुणवत्ता बढ़िया होने से बाजार में उन्हें बेहतर मुल्य मिला और शुद्ध लाभ भी करीब 25-30 प्रतिशत अधिक प्राप्त हुआ. डॉ कुमार कहते है कि खड़ी फसल में भी पोटाश के कमी के लक्षण को आसानी से पहचानी जा सकती है. फसल की पत्तियों का किनारा कटा - फटा और अग्र भाग भूरा होना, पत्तियाँ आकार में छोटी, पुरानी पत्तियों का अग्र भाग नुकीला और किनारे पीली होने लगना, पत्तियों का मुरझा कर सुखना आदि खड़ी फसल में पोटाश के कमी के लक्षण होते है. जिसे खड़ी फसल पर 1-2 प्रतिशत पोटैशियम सल्फेट का छिड़काव कर उपचार किया जा सकता है. मृदा वैज्ञानिकों द्वारा वर्षो शोध के बाद फसलों के लिए आवश्यक पोटाश उर्वरक की मात्रा की अनुशंसा की गई है. कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इसके आधार पर धान, मकई, गेहूँ एवं सोयाबीन में 40 किलो पोटाश / हे., अरहर, चना, मसूर में 25 किलो पोटाश / हे., रागी, कुल्थी, मूंगफली, तिल, तीसी, उरद में 20 किलो पोटाश / हे., राई, सरसों, तोरिया में 10 किलो पोटाश / हे., टमाटर एवं भिन्डी में 50 किलो पोटाश / हे., बंधागोभी एवं फूलगोभी में 60 किलो पोटाश / हे., मटर, फ्रेंचबीन, कद्दू, नेनवा, झींगी एवं खीरा में 40 किलो पोटाश / हे. तथा गन्ना में 60 किलो पोटाश / हे. की दर से पोटाश उर्वरक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।

डॉ कुमार ने किसानों को उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से भूमि में संचित पोषक तत्व भंडार के दोहन से बचने की सलाह दी है. सफल टिकाऊ खेती, गुणवत्ता वाले उत्पाद एवं बेहतर लाभ के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों के साथ कम्पोस्ट का प्रयोग करने को कहा. झारखण्ड की भूमि अम्लीय प्रकृति होने के कारण उपज में कमी देखी जाती है. किसानों को बुवाई से पहले खेत में 3-4 टन /एकड़ चुना या डोलोमाइट का प्रयोग करने की बात कही. ध्यान रहे म्युरिएट ऑफ़ पोटाश एक पोटाशधारी उर्वरक है और इसके अधिक प्रयोग से फसल को कोई नुकसान नहीं होता ।●

E ZONE CARE

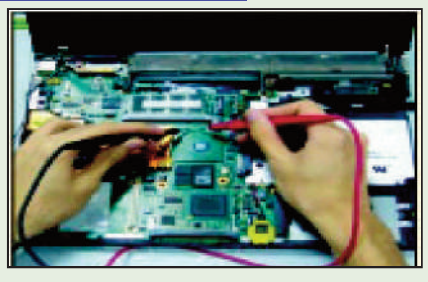

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

भगीरथ प्रयास करने होंगे

कोविड 19 यानि कोरोना वायरस से बचने के लिये पूरी मानव जाति संघर्षरत है। चीन से पैदा हुयी ये आपदा कोरिया, जापान को तबाह करते हुये यूरोप पहुंची और यूरोप को बर्बाद करते हुये अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी देशों तक को तबाह कर रही है। आज खाड़ी के देशों में इरान इसका सबसे बड़ा शिकार है और भारत भी इसकी काली छाया से बचा नहीं है। हम अब तक यही खैर मना सकते हैं कि कोरोना की व्यापक मार अब तक भारत पर नहीं पड़ी है लेकिन भारत बुरी तरह से उसके निशाने पर है। यहां अगर इसका संक्रमण हुआ तो मामला हाथ से निकल जायेगा। एक अर्द्धविकसित विशाल देश जिसकी आबादी 130 करोड़ हो , जहां 28000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है और जहां अस्पतालों में आम दिनों में भी बेड के अभाव में जमीन पर लिटा कर ईलाज होता हो वहां आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के मारक होते ही हमारी क्या गति होगी?

अभी सरकार को कोसने और उससे किसी चमत्कार की बजाय हम सारे भारतीयों को ही इससे निबटने के लिये संयुक्त प्रयास करने होंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है बल्कि अनुशासन और संयम भरा काम है। आखिर प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर हमने जनता कर्फ्यू को सफल बनाया है। भारत जैसे अव्यवस्थित देश में ऐसा अनुशासन अपने आप में एक सुखद बात है। आम भारतीय अगर स्वयं में यह संकल्प ले लेवे कि हम घरों में ज्यादा रहेंगे, संक्रमण के किसी भी संभावना के प्रति सतर्क रहेंगे, अफवाहों से दूर रह कर, सेनिटाइजेशन पर ध्यान देंगे, खुद के संक्रमण की आशंका पर तुरंत खुद को सबसे अलग कर लेंगे, दुसरे के संक्रमित होने पर तुरंत पुलिस को सुचित करेंगे। अनावश्यक यात्रा से बचेंगे, जांच में सहयोग करेंगे। इन सबके अलावा जो हम भारतीयों के लिये सबसे बड़ा खतरा है वो ये कि ***मुझे कुछ नहीं होगा?*** इससे बचना है। क्योंकि इसी लापरवाही का नतीजा आज इटली और यूरोप भुगत रहे हैं। आखिर उन्हें भी तो यही दंभ था कि उन्हें कुछ नहीं होगा ।

कोरोना का कोई ईलाज नहीं होने के कारण और इसके वायरस के काफी शक्तिशाली होने के कारण यह बहुत खतरनाक है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे संक्रमित व्यक्ति दो से चौदह दिन तक जांच में निगेटिव आ सकता है। इसलिये चार पांच दिन के अंतराल पर उसे बार-बार जांच करवानी पड़ सकती है। एक बार जांच में चार से पांच हजार रूपये का खर्च भारत में बहुत बड़ा बोझ है। देश भर में महज 75 जांच केंद्र हैं। ऐसे में सावधानी से बेहतर कोई समाधान नहीं। और ये सावधानी किसी एक व्यक्ति , समूह की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सभी भारतीयों को मिलकर भगीरथ प्रयास करने ही होंगे।

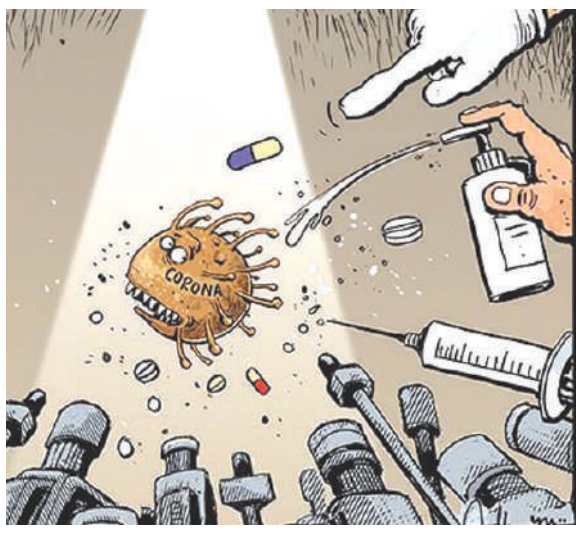

तीन अरब साल पहले पृथ्वी जलमग्न थी?

नेचर जिओसाइंस में छपे एक अध्ययन के अनुसार, तीन अरब साल पहले पृथ्वी एक वैश्विक महासागर से ढकी हो सकती है, जिसके चलते यह ग्रह ''जल संसार'' जैसा था। यह निष्कर्ष वैज्ञानिकों को यह समझने में मददगार हो सकता है कि पृथ्वी पर एक-कोशिकीय जीव सबसे पहले कहां और कैसे पैदा हुए थे?अध्ययन के अनुसार, पृथ्वी के जीव-मंडल की उत्पत्ति और विकास को महासागरों के भौतिक और रासायनिक इतिहास द्वारा आकार दिया गया था। समुद्री रासायनिक चट्टानें (सेडिमेंट्स) और महासागर की कायांतरित चट्टानें (क्रस्ट) अपने अंदर इन इतिहासों के भू-रासायनिक रेकॉर्ड समेटे हैं और इस तरह, इनमें उस समय पृथ्वी को ढकने वाले समुद्री जल के बारे में सुराग जमा हैं। ये नतीजे पेश करने वाले वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पैनोरमा जिले में 3.24 अरब साल पुरानी समुद्री चट्टान का अध्ययन किया। उन्होंने 100 से अधिक रॉक सैंपल से जुटाए डेटा का विश्लेषण किया और महासागर की चट्टान में रही ऑक्सीजन की किस्म का अध्ययन किया।

शोधकर्ताओं ने ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स ऑक्सीजन-16 और थोड़ा भारी ऑक्सीजन-18 का का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि तीन अरब साल पहले जब यह चट्टान बनी थी तो उस समय समुद्री जल में ऑक्सीजन-18 के परमाणु अधिक थे।वैज्ञानिकों के अनुसार, मिट्टीयुक्त जमीन में ऑक्सीजन के भारी आइसोटोप को सोखने की क्षमता होती है। चट्टानों में पाई गई ज्यादा ऑक्सीजन-18 से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आइसोटोप को सोखने के लिए ज्यादा भूमि नहीं रही होगी। वैज्ञानिकों ने जर्नल में लिखा है, ''महाद्वीपों के बनने से पहले शुरुआती पृथ्वी 'जल संसार' जैसी रही होगी, जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास में पर्यावरणीय बाधा बनी, जो कि अन्यथा संभव होता। हालांकि, वैज्ञानिकों ने कहा है कि इन निष्कर्षों का अर्थ यह नहीं है कि पृथ्वी उस समय पूरी तरह से भूमिहीन थी। उन्हें संभावना जताई है कि कुछ जमीन समुद्र से ऊपर रही होगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी हम आज देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, ये निष्कर्ष अरबों साल पहले समुद्र के पानी की रासायनिक बनावट के बारे में पता लगाने का सुराग देते हैं।

जलवायु परिवर्तन है मुख्य संकट

कपिल शगुन

22 मार्च विश्व जल दिवस है। जल की हमारे जीवन में क्या महत्ता है ये हम सभी जानते हैं। हाल के कुछ वर्षों में इसके संरक्षण को बहुत सारे लोग आगे आये हैं, पर अभी बहुत कुछ किसा जाना बाकी है। अभी तो जलवायु परिवर्तन से जल की उपलब्धता पर जो संकट है हमें उससे निबटना है।

संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन से पानी की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से वैश्विक खाद्य उत्पादन का मौलिक स्वरूप बदल सकता है। इस तरह आने वाले समय में मौसम में छोटे से छोटा बदलाव भी खाद्य असुरक्षा (खाद्य कीमतों में वृद्धि) और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की घटनाओं को बढ़ा सकता है।

स्थानीय मौसम के स्वरूप में बदलाव की वजह से वर्ष 2040 तक चार प्रमुख फसल जैसे गेहूं, चावल, सोयाबीन और मक्का के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने वाला है। इस प्रभाव को नेशनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (पीएनएस) में मई महीने में प्रकाशित शोध में दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र कहती है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसे देशों में इन चार प्रमुख फसल वाले खेत या तो हमेशा सूखे में रहेंगे या तो अत्यधिक बारिश की वजह से डूब क्षेत्र बन जाएंगे।उदाहरण के लिए, 2020 और 2060 के बीच, भारत में इस वक्त गेहूं की खेती के लिए उपयोग में आने वाली 30 प्रतिशत भूमि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के वर्तमान रुझानों के तहत अधिक वर्षा प्राप्त करेगी। दूसरी तरफ मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के 87 से 99 फीसदी तक गेहूं वाले खेत कम बारिश ग्रहण करेंगे।

अनुमानों में दिखाया गया है कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के हिस्से सूख जाएंगे, जबकि उष्णकटिबंधीय और उत्तर में ओले गिरेंगे। भारत के लिए रुझान यह भी दर्शाता है कि चावल की खेती के लिए उपयोग होने वाली भूमि का 100 प्रतिशत, मक्का का 91 प्रतिशत और सोयाबीन का 80 प्रतिशत हिस्सा अगले 40 वर्षों के भीतर अत्यधिक बारिश वाली परिस्थितियों का सामना करेगा। इससे यह साबित होता है कि कृषि कार्य की बढ़ती दर और दिनों-दिन मौसम के बढ़ते जोखिम और बदलाव से अगले 50-100 साल काफी कठिन होने वाले हैं। आने वाले समय में तापमान और वर्षा में दीर्घकालीन बदलाव खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता का कारण हैं।

बावजूद इस तथ्य के कि वैश्विक खाद्य प्रणाली सामान्यतः बढ़ती कैलोरी की मांग को पूरा करती रही है, यह रिपोर्ट कहती है कि 82.1 करोड़ लोग (विश्व जनसंख्या का 11 फीसदी) कुपोषित ही हैं, और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर में प्रमुख कृषि प्रणालियां, चाहे वह अर्ध शुष्क भारतीय उपमहाद्वीप हो, या उत्तरी अफ्रीका के मध्य क्षेत्र हों, सभी जलवायु परिवर्तन से पैदा हुए प्रभावों के लिए अत्यधिक असुरक्षित हैं।मानसून प्रभावित भारतीय उप महाद्वीप में जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश में बढ़ोतरी बाढ़ की स्थिति पैदा करती है और इसकी कमी से सूखा और अत्यधिक तापमान की स्थिति बनती है। बर्फ के पिघलने से पैदा पानी पर निर्भर खेती जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र से जुड़ी खेती आती है, वहां यह असुरक्षा और अधिक है। हालांकि, इस परिस्थिति से बचने की गुंजाइश पहले वाले मामले में काफी सीमित है।

मानसून रहित उप सहारा अफ्रीका को असुरक्षा के मामले में सबसे अधिक असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है, जिसकी वजह से उपज में कमी आ सकती है। साथ ही, बाढ़ या सूखा की घटनाएं बढ़ सकती है। पिछले 20 वर्षों में जमीनी सतह पर स्थित जल में कमी, भूजल की मात्रा में कमी, बारिश के चरम दिनों में वृद्धि या कमी और उससे उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति जैसे बदलाव जलवायु परिवर्तन के प्रवाहक हैं, और इससे उत्पादकता कम हो रही है। यह रिपोर्ट कहती है कि वर्षा की अस्थिरता, और विशेष रूप से इसकी तीव्रता, बरसने की अवधि और बार-बार बरसने की आवृत्ति से कृषि की उत्पादकता पर असर हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से पानी और और पानी की कमी या अधिकता से कृषि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। दुनिया के कई क्षेत्रों में पानी की कमी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है।

जल प्रबंधन कृषि कार्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और फसल उत्पादन के लिए फसल चक्र में बदलाव कर कभी नकदी फसल तो कभी मुख्य खाद्य फसलों को उगाना जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए कृषि जल प्रबंधन के लिए दोहरी चुनौती है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली चुनौती कृषि के वर्तमान स्वरूप को अपनाकर पानी की कमी और अधिकता (सूखा और बाढ़) की स्थिति से निपटने के लिए सूखे की स्थिति में पानी की उपलब्धता और बाढ़ की स्थिति में जल निकासी है। दूसरी चुनौती ग्रीन हाउस गैस को कम कर जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को कम करने की है। यह 2017 के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की लंबी अवधि के अनुमानों को भी सामने लाता है, जिसमें कहा गया है कि कम और मध्यम आय वाले देशों विशेषरूप से मध्य पूर्व में कैलोरी की मांग एक साथ बढ़ेगी और जलवायु जोखिमों में बढ़ते हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पादन जोखिम भी बढ़ेगा।

रिपोर्ट कहती है कि महज पानी की उपलब्धता में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर योजना बनाने से कृषि उत्पादकता में मन मुताबिक फल नहीं मिलेगा। पानी को जलवायु परिवर्तन रोकने के दूसरे स्मार्ट तरीकों के साथ देखना होगा और जरूरी कदम उठाने होंगे। पूरे जल चक्र में बदलाव को इस तरह से लाना होगा ताकि यह कृषि की उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव लाने के साथ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को भी कम कर सके।

महामारी से लेकर प्रलय तक के लिए तैयार है आर्कटिक वॉल्ट

किसी महामारी के फैलने या परमाणु युद्ध छिड़ने की स्थिति में खाने का संकट पैदा होने पर यह गुंबद काम आएगा पृथ्वी के सुदूर आर्कटिक क्षेत्र में स्थित इस इमारत में दुनिया भर से लाकर अनाज की अहम किस्मों को रखा जाता है.

हाल ही में आर्कटिक में बने अपनी तरह के इस खास स्टोर रूम में बीज की दस लाखवीं किस्म को जोड़ा गया है. वॉल्ट कहलाने वाले इस खास गुंबद में अनाजों की अलग अलग किस्में बचा कर रखी जाती हैं ताकि किसी संकट की स्थिति में इस खजाने से उसके बीज निकाले जा सकें और उन्हें मानवता के लिए फिर से उपलब्ध कराया जा सके. यहां रखे बीजों को खराब होने से बचाने के लिए इसके दरवाजे भी बहुत कम ही खोले जाते हैं. विश्व भर में खाने की चीजों की आपूर्ति निर्बाध गति से बनाए रखने में इसकी अहम भूमिका मानी जाती है. असल में हम अपनी ऊर्जा की ज्यादातर जरूरत के लिए कुछ गिनती के अनाजों पर ही निर्भर करते हैं. आर्कटिक इलाके में स्थित स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में चावल, गेहूं और कुछ अन्य प्रमुख अनाजों की किस्में रखी गई हैं.

साल 2008 में एक पहाड़ के पास बनाई गई इस स्टोरेज फेसिलिटी की शुरुआत इस मकसद से की गई थी कि अगर कभी परमाणु युद्ध छिड़ जाए या कोई महामारी फैल जाए तो उस स्थिति में प्रभावित इलाकों में फिर से उगाने के लिए खाद्यान्नों की किस्में बचाई जा सकें. इसीलिए इसका लोकप्रिय नाम "डूम्स डे वॉल्ट" यानि प्रलय गुंबद है. यह जगह नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच में स्थित है और यहां गिनती के इंसान ही रहते हैं. साल में केवल कुछ ही बार इसके दरवाजे खोले जाते हैं ताकि बीजों की देखभाल के लिए जो जरूरी काम हों वे किए जा सकें.हाल के समय में 25 फरवरी 2020 को इसे खोला गया जब भारत, माली और पेरू के 30 जीन बैंकों की ओर से लाए गए बीज यहां जमा करवाए गए. लेकिन ऐसी आपातकालीन स्थिति के अलावा शांतिकाल में भी इसके कुछ इस्तेमाल होते हैं. जैसे कि अगर कभी पौधों की नई किस्में विकसित करने वाले ब्रीडरों को जरूरत हो तो उन्हें यहां से बैक अप किस्में मुहैया कराई जाती हैं.

पहले के समय में विश्व में 7,000 विभिन्न तरह के पौधे उगाए जाते थे. विशेषज्ञ बताते हैं कि अब इंसान अपनी ऊर्जा की 60 फीसदी जरूरत केवल तीन मुख्य किस्मों - मक्का, गेहूं और चावल - से ही लेने लगा है. इसका बुरा पहलू यह है कि जलवायु परिवर्तन के चलते उपज खराब होती है तो पूरी आबादी की फूड सप्लाई प्रभावित होगी.वॉल्ट का प्रबंधन करने वाले जर्मनी के बॉन में स्थित संगठन क्रॉप ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक श्टेफान श्मित्स कहते हैं(

धरती पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की वैश्विक प्रणाली का बैक अप है सीड वॉल्ट."

संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार, आज भी विश्व में हर नौ में से एक व्यक्ति रात को भूखा सोने को मजबूर है. वैज्ञानिक बता चुके हैं कि मौसम के अनियमित पैटर्न से आगे चल कर दुनिया में खाने की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही घटती जाएगी.सन 2015 में ऐसी नौबत आई थी जब पहली बार रिसर्चरों को वॉल्ट से बीज निकालने पड़े थे. सीरिया के गृह युद्ध के दौरान जब अलेप्पो शहर की तबाही में वहां के सीड बैंक भी नष्ट हो गए तो वॉल्ट से बीज निकाले गए थे. दो साल बाद इन बीजों को उगाकर फिर से उस-ाका सैंपल स्वालबार्ड वॉल्ट में जमा कराया गया.

बीते साल नॉर्वे ने करीब एक साल तक चले इस इमारत के अपग्रेड प्रोग्राम में 1.1 करोड़ डॉलर खर्च किए. आर्कटिक के बेहद ठंडे माहौल में इसे यह सोच कर बनाया गया था कि अगर संकट की स्थिति में पावर फेल हो जाए तो भी यहां रखे बीज जल्दी खराब नहीं होंगे. लेकिन असल में अब आशंका यह भी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण खुद प्रलय गुंबद पर भी मुसीबत आ सकती है.

मछलियों के तैरने का होता है एक खास तरीका

चीटियों से लेकर भेड़, हिरण, और हाथी जैसे जीव समूह में एक खास तरह का पैटर्न बनाकर चलते हैं। एक ही दिशा में समन्वित तरीके से तैरती हुई मछलियों के झुंड में भी कुछ इसी तरह की सामूहिक समझदारी देखने को मिलती है। जीव समूहों के इस व्यवहार का अध्ययन ट्रैकिंग के आधुनिक तरीकों और छवियों के विश्लेषण से किया जाता है, जबकि शोर या ध्वनि को नजरअंदाज कर दिया जाता है।समूह में जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते समय वैज्ञानिक आमतौर पर ध्वनि या शोर को बाधा के रूप में देखते हैं। लेकिन, सिक्विड मछलियों पर किए गए भारतीय वैज्ञानिकों के एक नये अध्ययन में इस धारणा के विपरीत तथ्य उभरकर आए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि मछलियां जब समूह के दूसरे सदस्यों के साथ क्रमबद्ध रूप से नहीं तैर रही होती हैं तो उनके व्यवहार में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न शोर अधिक होता है। यह बिखरकर तैरने के बजाय क्रमबद्ध रूप से तैरने का संकेत होता है।भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलूरू के शोधकर्ताओं द्वारा किये गए इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि समूह में मछलियां जितनी कम होती हैं, शोर उतना ही अधिक होता है। इसीलिए, मछलियों के एक साथ तैरने की संभावना ज्यादा होती है। प्रकृति तथा जीवों के व्यवहार के बारे में इस तरह की जानकारी रोबोटिक समूह और व्यापक जनसमूह के बीच सूचनाओं के प्रसार से जुड़े अध्ययन में उपयोगी हो सकती है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि ध्वनियां यह समझने में मददगार हो सकती हैं कि जीव समूहों के जटिल व्यवहार कैसे सामान्य व्यक्तिगत व्यवहारों से उभरते हैं। सिक्विड मछलियों के समूह द्वारा भोजन की तलाश एवं शिकारियों से बचाव के लिए तालमेल बनाए रखकर समान दिशा में एक साथ तैरने जैसे व्यावहारों का हवाला देते हुए वैज्ञानिकों ने यह बात कही है।

उत्तर बंगाल में बढी गिद्धों की संख्या

पिछले दो दशक से उत्तर बंगाल में गिद्ध दिखने बंद हो गए थे, लेकिन पिछले दिनों जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के सीमा पर बागराकोट में 200 से ज्यादा गिद्ध देखे गए,। बागराकोट में हिमालयन ग्रिफॉन और ह्वाइट-बैक्ड दोनों प्रजाति के गिद्ध दिखे हैं। 20 साल बाद इन गिद्धों की बागराकोट में वापसी को वन विभाग के अधिकारी अच्छा संकेत मान रहे हैं और उनका कहना है कि आनेवाले दिनों में इनकी तादाद बढ़ेगी। जालदापाड़ा वाइल्डलाइफ के डीएफओ कुमार विमल ने बताया कि वन क्षेत्र के संरक्षण के चलते वन्य प्राणियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इनकी संख्या बढ़ने से गिद्धों को आसानी से भोजन मिल जा रहा है। इस से उन्हें इस क्षेत्र की आबोहवा रहने लायक लग रही है।

शिशु मधुमक्खियों के मस्तिष्क के विकास को नुकसान पहुंचा रहे हैं कीटनाशक

एजेंसियां :एक नए अध्ययन में पाया गया है कि मधुमक्खियों के लार्वा चरण के दौरान कीटनाशकों के संपर्क में आने से उनके मस्तिष्क के विशेष भागों पर इसका खतरनाक असर पड़ता है

मधुमक्खियों के लार्वा चरण के दौरान कीटनाशकों के संपर्क में आने से उनके मस्तिष्क के विशेष भागों पर इसका खतरनाक असर पड़ता है। इस-ाका पता इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने माइक्रो-सीटी स्कैनिंग तकनीक का इस्तेमाल करके पता लगाया है।अधिकतर अध्ययनों ने वयस्क मधुमक्खियों पर कीटनाशक के खतरों का परीक्षण किया है, क्योंकि ये सीधे कीटनाशक से दूषित फूलों का रस (मकरंद) और पराग इकट्ठा करते हैं। लेकिन नए अध्ययन से पता चला है कि कॉलोनी में वापस लाए गए दूषित भोजन के प्रभावों से शिशु मधुमक्खियों के विकास पर असर पड़ता है, जिससे वे बड़े होकर जीवन में सही ढ़ंग से कार्य नहीं कर पाती हैं।इंपीरियल में जीव विज्ञान विभाग के प्रमुख शोधकर्ता डॉ. रिचर्ड गिल ने कहा कि मधुमक्खियों की कॉलोनी सुपरऑर्गेनिज्म के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए जब कोई भी विष कॉलोनी में प्रवेश करता है तो इसका सीधा असर शिशु मधुमक्खियों पर पड़ता है। यह अध्ययन प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल सोसायटी बी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

जब युवा मधुमक्खियां कीटनाशक-दूषित भोजन करती हैं, तो इनके मस्तिष्क के कुछ हिस्से कम विकसित होते हैं, जिसके कारण वयस्क मधुमक्खियां सही ढ़ंग से काम नहीं कर पाती हैं, यह ऐसा प्रभाव होता है जो हमेशा बना रहता है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि कैसे कीटनाशकों के संपर्क में आने से कॉलोनियां प्रभावित होती हैं, क्योंकि जब युवा मधुमक्खियां वयस्क होती हैं तो वे ठीक से भोजन करने में सक्षम नहीं होती हैं। यह अध्ययन कीटनाशकों के उपयोग पर जरुरी दिशानिर्देशों पर प्रकाश डालता है। कॉलोनी में फूलों के रस के बजाय न्यूटीनोटिनोइड्स नामक कीटनाशकों के एक वर्ग का छिड़काव किया गया था। ये कीटनाशक कुछ यूरोपीय संघ के भीतर प्रतिबंधित हैं लेकिन दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। मधुमक्खी के अपने प्यूपा से युवा और युवा से वयस्क होने के दौरान, उनकी सीखने की क्षमता का तीन दिनों के बाद और 12 दिनों के बाद जांच की गई, और कुछ ने प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में माइक्रो-सीटी तकनीक का उपयोग करके उनके दिमाग का चित्र खीचा गया।इन परिणामों की तुलना उन कॉलोनियों के युवाओं से की गई, जिन्होंने कोई कीटनाशक भोजन नहीं किया था, और जिन्हें एक बार वयस्क होने के बाद ही कीटनाशक खिलाया गया था। जब वे लार्वा के रूप में विकसित हो रहे थे, तब मधुमक्खियों को कीटनाशक खिलाया गया था, उनमें सीखने की क्षमता में काफी कमी थी, जबकि युवा अवस्था में कीटनाशक खिलाने पर असर लार्वा अवस्था की तुलना में कम दिखा।

शोधकर्ताओं ने अलग-अलग कॉलोनियों से करीब 100 मधुमक्खियों के दिमाग को स्कैन किया। जिन मधुमक्खियों को कीटनाशकों के संपर्क में लाया गया था, उनके मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बहुत छोटा था, जिसे मशरूम बॉडी के रूप में जाना जाता है। मशरूम बॉडी या कॉर्पोरा पेडुंकलता कीड़ों के मस्तिष्क में बनी संरचनाओं की एक जोड़ी होती है। मशरूम बॉडी कीड़ों में सीखने की क्षमता के लिए जाना जाता है, और छोटा मशरूम बॉडी होने का मतलब है कि वह कम सीखेगा जिससे उस-ाका कार्य सही से नहीं हो पाएगा।

प्रमुख शोधकर्ता तथा इंपीरियल में जीव विज्ञान विभाग से डॉ. डायलन स्मिथ ने कहा कि इस बात के बहुत अधिक सबूत हैं कि मधुमक्खियों के कॉलोनियों के अंदर कीटनाशक बढ़ रहा है। अध्ययन के अनुसार से ऐसे वातावरण में पाले जा रहे मधुमक्खियों को होने वाले खतरों का पता चलता है। कीटनाशकों के संपर्क में आने पर कॉलोनी में आगे चलकर मधुमक्खियों की संख्या कुछ सप्ताह बाद प्रभावित हो सकती है।

संकल्प, संयम , जनभागीदारी से करेंगे इस महामारी से मुकाबला :हेमन्त सोरेन

रांची : मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंडवासियों की सुरक्षा हेतु सरकार जरूरी कदम उठा रही है। सभी जिला के उपायुक्त स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे । हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य के लोग कोरोना वायरस से संबंधित अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। वर्तमान सरकार हर एक की सुरक्षा हेतु जरूरी कदम उठा रही है। पंचायतों में आइसोलेशन वार्ड तैयार करने का निर्देश दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह 22 मार्च की सुबह से लोग अपने घरों में हैं। यह जनसहयोग ही तो है। इस जनसहभागिता को हमें और मजबूत करना है। हमें यह संकल्प लेना है कि रात में भी राज्य के लोग अपने घरों में रहेंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जिला के उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। उक्त निर्देश का पालन उपायुक्त अपने स्तर से पूरा करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि रात में किसी तरह का कार्यक्रम या लोगों का जुटान न हो।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विभाग से आग्रह किया है कि देश में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति में यात्रा करना मुनासिब नहीं है। इसलिए झारखण्ड समेत देश के अन्य राज्यों के छात्रों को हो रही परेशानी को समझते हुए छात्रावासों को बंद ना करने की हिदायत दी जाए। मुख्यमंत्री ने झारखंडवासियों से कहा कि अपने-अपने घरों में रहना कोरोना वायरस को रोकने का सबसे अचूक हथियार है। राज्य की जनता अपने आस पास रह रहे गरीबों की यथा सम्भव मदद करे। याद रखें साथियों कि आपके सहयोग से ही हम इस महामारी को फैलने से रोक सकते हैं।

स्व0 जे.पी. चौधरी की पुण्यतिथि मनाइ गई

रांची :20 मार्च को छात्र क्लब ग्रुप के तत्वावधान में प्रसिद्ध समाजसेवी एवं जे.पी. हुण्डई के संस्थापक स्व0 जे. पी. चौधरी का अष्टम पुण्यतिथि के अवसर पर पिस्कामोड़, ईटकी रोड, रातु रोड में 101 मास्क फुटपाथ के कपड़ा, चाय, सब्जी, पुष्प, फल, बिक्रेताओ के बीच में बांटी गई। साथ ही उन्हे कोरोना वाइरस से बचाव के लिए टिप्स भी दिये गये। क्लब के संरक्षक नीलम शर्मा ने कहा अपने हाथो को दिन में दो-तीन बार साबुन, सैनिटाइजर, डिटॉल से साफ करते रहे, भीड़-भाड़ वाले स्थलो पर जाने से परहेज करे, किसी भी तरह के अफवाहो पर ध्यान न दे, अपने आस-पास के इलाकों को स्वच्छ रखे, शरीर में यदि सर्दी, खॉसी, बुखार, गले मे तकलीफ, सांस लेने मे तकलीफ आदि लक्षण पाये जाये तो इसे नजर अंदाज न करे, निकटवर्ती डॉक्टरो से अपनी जाँच कराये, डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुख एवं नाक को रूमाल या कपड़े से ढ़के रहे साथ ही अगर आप स्वस्थ है तो आपको मास्क पहनने कि आवश्यकता नहीं हैं। अपने किसी भी बीमारी को न छुपाये खुलकर डॉक्टर को अपनी समस्या बतलाये, अपने नाक, कान मुंह को बार-बार न छुएं एवं एक दुसरे से दुरी बनाए रखे।

101 मास्क वितरण किया

इसके पुर्व कार्यक्रम का शुभारंभ स्व0 जे.पी चौधरी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम कि अध्यक्षता शिव किशोर शर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्यरूप से बिनोद कुमार साहु, शैलबाला, मन्नु चौधरी, संजीव कुमार साहु, संतोष कुमार, संतोष प्रसाद गुप्ता, राजा गुप्ता, सुबोध चौधरी, विकाश कुमार वेदान्त, तान्या चौधरी उपस्थित थे।

कोरोना से निबटने के लिये उपायुक्त ने की बैठक

संवाददाता

रांची : नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु उपायुक्त रांची राय महिमापत रे की अध्यक्षता में गोपनीय शाखाा में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। बैठक में वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिला स्तर पर बनाये गये सभी कंट्रोल टीम के वरीय/नोडल पदाधिकारी उपस्थित हुए। वैश्विक महामारी घोषित नोवल कोरोनावायरस (कोविड-19) की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने पदाधिकारियों से कहा कि वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए प्रोटोकॉल का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कम्यूनिटी स्टेज पर वायरस के पहुंचने पर इसके सभी पहलुओं को देखते हुए अपनी तैयारी पूरी रखें। बैठक में उपायुक्त ने जिले में नोवल कोरोना वायरस से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग को अपनी सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश देते हुए आईसोलेशन एवं क्वारनटाइन सेंटर्स की स्थिति की विस्तृत जानकारी लेते हुए क्वारनटाइन जोन बनाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जहां भी होम क्वारनटाइन की जानकारी मिली है, वहां पोस्टर चिपकाएं जाये, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में उन्होंने सिविल सर्जन को सूची देने का निदेश दिया। डीपीएम को ग्रामीण इलाकों में पोस्टर लगाने का निदेश उपायुक्त की ओर से दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ

समन्वय स्थापित कर प्रत्येक प्रखंडों में क्वारनटाइन एवं आईसोलेशन सेंटर हेतु भवन चिन्हित करने का निर्देश दिया। साथ ही दूसरे भवनों को भी क्वारनटाइन जाने बनाने को लेकर चर्चा की गयी।

बैठक में उपायुक्त ने सिविल सर्जन से जिले में संचालित आइसोलेशन वार्ड में वेंटीलेटर की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। साथ ही आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति हेतु सिविल सर्जन एवं नजारत पदाधिकारी को निदेशित किया। बैठक में उपायुक्त ने कोरोनावायरस के मरीजों को त्वरित चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया। साथ ही उन्होंने गैर सरकारी एम्बुलेंस को भी चिन्हित करने को कहा।

बैठक में उपायुक्त ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखने हेतु जिला स्तरीय टीम का गठन किया जाएगा। जो जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कोरोनावायरस के प्रकोप से बचाव एवं बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखने का कार्य करेगी। जिले में क्वारनटाइन एवं आईसोलेशन सेंटरों में विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स के संग्रहण व अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए एक टीम का गठन किया जाएगा। बैठक में डीडीसी ने सेंटरों में विशेष रूप से सैनेटाइजर, मास्क, पर्याप्त मात्रा में बेड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि क्वारनटाइन जोन, आईसोलेशन सेंटर एवं लॉजिसटिक्स पर विशेष ध्यान दें। साथ ही उन्होंने क्वारनटाइन वर्कर को लेकर नर्सिंग कॉलेजों से कर्मियों की सूची मंगवाकर कार्य करने का निदेश दिा। बैठक में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) को लेकर उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निदेशित किया। उपायुक्त ने जिलावासियों को कोरोनावायरस के प्रति जागरूक करने के लिए माइकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार किए जाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम किये जाये। बैठक में उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी से बस पड़ावों में वाहनों को सैनिटाइज किये जाने की जानकारी ली। उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव और फैलाव की रोकथाम हेतु सभी यात्रियों की साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया। साथ ही उपायुक्त ने समय-समय पर सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, बस स्टैण्डों इत्यादि की साफ-सफाई करवाने को कहा।

कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त ने मेडिकल क्यूरी टीम के बारे में डीआईओ से जानकारी ली। डीआईओ ने बताया कि टीम तीन शिफ्ट में काम करेगी। साथ ही डीआईओ को रिम्स और सदर अस्पताल के साथ समन्वय स्थापित कर कंट्रोल रुम संचालित करने को लेकर निर्देश दिया गया।

ओला वृष्टि में फसल बर्बाद हुए किसानों को मिलेगा मुआवजा

- अंचलाधिकारियों को किसानों का क्षति आकलन करने का निर्देश।
- सभी अंचलाधिकारियों को आकलन कर, राज्य आपादा मोचन निधि के लिए अधियाचना समर्पित करने का निर्देश।
- अंचल कार्यालय में हेल्प डेस्क लगा कर किसानों से आवेदन प्राप्त करेंगे अंचलाधिकारी।

रांची : बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि की वजह से जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई उन्हें जिला प्रशासन द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के तहत मुआवजा दिया जाएगा। उपायुक्त रांची श्री राय महिमापत रे ने इस संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को निदेश जारी करते हुए कहा कि सभी अपने अपने कार्यालय में हेल्प डेस्क लगा कर किसानों से लाभुक किसानों से आवेदन प्राप्त कर उक्त हेतु 18 मार्च तक अधियाचना समर्पित करेंगे।

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, रांची राय महिमापत रे ने रांची के सभी अंचलाधिकारियों को अपने अपने कार्यालय में हेल्प डेस्क लगा कर किसानों से आवेदन प्राप्त करने को कहा है, जिनकी फसल बेमौसम लगातार हुई बारिश एवं ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गयी थी। साथ ही इससे संबंधित अधियाचना जिला आपदा कार्यालय को 18 मार्च से पूर्व समर्पित करने का निदेश दिया है। ताकि किसानों को जरूरी मुआवजा दिया जा सके।

गौरतलब है कि बीते हफ्ते रांची सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश एवं ओलावृष्टि की वजह से भारी मात्रा में किसानों की फसल बर्बाद हुई थी। जिसपर संज्ञान लेते हुए रांची जिला प्रशासन ने अंचलाधिकारियों को इस संबंध में जरूरी आदेश जारी किया और किसानों को राहत दिलाने हेतु पहल की गई।

रेलवे ने बिना स्टेशन आये टिकट के पैसे रिफंड करने की सुविधा का इंतजाम किया

रांची संवाददाता : कोरेना वायरस के संक्रमण को ध्यान मे रखते हुए रेल मंत्रालय द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है के रेलवे स्थानों पे टिकट रिफंड करने हेतु अतिरिक्त भीड़ ना हो, इसलिए रेल्वे स्टेशनों पर स्थित कंप्यूटराइज्ड आरक्षण कार्यालय खिड़की से प्राप्त टिकटों की वापसी के लिए नियमों मे सहूलियत दी गयी है ।

- ऑनलाइन एवं-टिकट के लिए नियम पूर्ववत है, क्योंकि टिकट वापसी के लिए यात्रियों को स्टेशन पर आने की आवश्यकता नहीं होती है ।
- नियमों की सहूलियत केवल दिनांक 21-03-2020 से दिनांक 21-06-2020 (3 महीने) के अवधि के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ही होगी । दिनांक 21-03-2020 से दिनांक 21-06-2020 (3 महीने) तक रेल्वे द्वारा रद्द की गयी ट्रेनों के लिए : अपनी यात्रा दिनांक से (3 महीने) के भीतर रिफ़ंड काउंटर से अपना टिकट जमा करके यात्री रिफ़ंड ले सकते है। (पहले यह नियम टिकट रिफंड करने हेतु 3 दिन (72 घंटे) का था)
- रेल्वे द्वारा ट्रेन रद्द नहीं की गयी और यात्री ने अपनी यात्रा भी नहीं की , अपनी यात्रा दिनांक से 3 महीने के भीतर स्टेशन पर टिकट डिपोसिट रिसीप्ट (TDR) द्वारा रिफ़ंड प्राप्त कर सकते है। (पहले यह नियम टिकट रिफंड करने हेतु 3 दिन का था)
- यात्री टिकट डिपोसिट रिसीप्ट (TDR) फ़ाइल करने के दिनांक से अगले 60 दिनो के भीतर चीफ़ क्लेम ऑफिस / चीफ़ कमर्शियल मैनेजर ऑफिस मे रिफ़ंड के लिए टिकट डिपोसिट रिसीप्ट (TDR) जमा कर सकते है (वर्तमान नियम के अनुसार पहले यह अवधि 10 दिन की थी)
- जिन यात्रियों को अपना टिकट 139 के माध्यम से रद्द करना है उन्हे 3 महीने के भीतर काउंटर से रिफ़ंड प्राप्त करना होगा। (वर्तमान नियम के अनुसार पहले यह अवधि ट्रेन खुलने के निर्धारित समय तक थी)

रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि उपरोक्त सुविधा का लाभ ले जिससे स्टेशन पर ना आकर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है।

कोराना वायरस से बचाव के लिए एसओपी तैयार करेगा सीसीएल : सीएमडी सीसीएल

संवाददाता

रांची : जिस तरह ''कोराना वायरस'' देश के विभिन्न राज्य में फैल रहा है उसको देखते हुये सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) निर्माण करने का निर्देश दिया है, जिससे सीसीएल वृहद परिवार एवं राज्यवासियों को ''कोराना वायरस'' से बचाव के लिए एतिहायत बरतना जरूरी है। इससे संबंधित आज 18 मार्च को सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस के प्रागंण में सीसीएल कर्मियों को 'कोरोना वायरस' के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया। इस अवसर पर सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह, निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, सीसीएल सीएमएस डॉ. सी.पी. धाम, डॉ. डी.के.एल. चौहान सहित सीसीएल के पूर्व सीएमएस डॉ. राकेश आर्या, डॉ. आर.आर. सिन्हा, डॉ. बि.एम.के. सिन्हा, डॉ. मजूश्री सिंह सहित बड़ी संख्या में सीसीएल कर्मी उपस्थित थे।

सीएमडी गोपाल सिंह ने 'कोर ग्रुप' बनाने का निर्देश देते हुये कहा कि एसओपी (Standard Operating Procedure) यथाशीघ्र निर्माण किया जाय जिससे सीसीएल मुख्यालय सहित सभी कमांड क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों को लाभ मिल सके और हम सभी कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित रहें। श्री सिंह ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति की पहचान अब तक झारखंड में नहीं हुई है। गोपाल सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यस्थल या अन्य जगह पर उचित दूरी बनाये रखें, जब

भी खांसी-सर्दी किसी कारण हो तो कोहनी का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वायरस वाटर ड्रॉपलेट के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर सकता है।

सीसीएल के सीएमएस डॉ सी.पी. धाम ने बताया कि जन आरोग्य केन्द्र में छः बिस्तर का व्यवस्था है जिससे जरूरतमंद लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जा सके। उन्होंने जानकारी दिया कि सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में कोराना वायरस से संबंधित पोस्टर आदि के माध्यम से कर्मियों एवं आमजन को जागरूक किया जा रहा है।

अवसर विशेष पर पूर्व सीएमएस डॉ. राकेश आर्या, डॉ. आर.आर. सिन्हा, डॉ. बि.एम.के. सिन्हा एवं डॉ मजूश्री सिंह ने ''कोराना वायरस'' के बारे में उपस्थित सभी को जागरूक किया और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित जारी स्वास्थ्य जानकारी जैसे बचाव के लिए क्या करें और क्या नहीं करें पर टिप्पणी किये। सभी ने उपस्थित कर्मियों से आग्रह किया कि हम सभी को कोराना वायरस के प्रति जागरूक रहना है और भारत सरकार द्वारा बताये गये सुझाव जैसे बार-बार हाथ धोना (Hand Hygiene), छिकते-खांसते समय विशेष सावधानी बरतना, मुंह, नाक और कान को अनावश्यक न छूना, जरूरत पड़ने पर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सेवा लेना, समूह में इक्कट्ठा होना आदि पर विस्तार जानकारी दिया गया। सभी ने यह भी सलाह दिया कि अनावश्यक कार्यलय संबंधी दौरा से परहेज करें।

कोरोना वायरस को लेकर उपायुक्त रांची ने जारी किया गाइडलाइन

- **उपायुक्त रांची की अध्यक्षता में कंट्रोल टीम का गठन**

रांची :कोविड-19/कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन समिति, रांची की अध्यक्षता में एक कंट्रोल टीम का गठन किया गया है। यह टीम विभिन्न उद्देश्यों से तैयार की गई अलग-अलग टीमों का निरीक्षण एवं प्लान तैयार करेगी।

इस गाइडलाइन के तहत कंट्रोल टीम के अलावा सिंगल विंडो हेल्पलाइन, पब्लिक अवेयरनेस एंड मीडिया सर्विलांस टीम, पेरिमेटर सर्विलांस टीम, ब्लॉक/पंचायत/वार्ड लेवल टीम, मटेरियल एन्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम, ह्यूमन रिसोर्सेज टूबलशूटिंग एवं क्वारेंटाइन मैनेजमेंट टीम, हेल्थ केयर सर्विलांस टीम। ये सभी टीमें मुख्य कंट्रोल टीम को दैनिक प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट करेंगे। मुख्य कंट्रोल टीम में उपायुक्त रांची श्री राय महिमापत रे के अलावा इस टीम में वरीय आरक्षी अधीक्षक रांची, उप विकास आयुक्त रांची, एसडीओ रांची, एसडीओ बुंडू, सिविल सर्जन रांची, डिस्ट्रिक्ट आईडीएसपी ऑफिसर रांची और यूनिसेफ के रीजनल कंसलटेंट, एनएचएम के प्रतिनिधि सहित रिम्स के डॉ0 मनोज कुमार इसके सदस्य होंगे।

दोषियों को सजा पर पुलिस को सम्मानित कर खुशिया मनाई

रांची : प्रसिद्ध समाज सेविका सुमन मिश्रा के नेतृत्व में निर्भया कांड के चारों दुष्कर्मियो को कोर्ट द्वारा फांसी दिए जाने की खुशी में सुखदेव नगर थाना प्रभारी संजय कुमार एवं पण्डरा थाना प्रभारी शशि रंजन कुमार जी को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं मिठाई खिलाकर सम्मानित कर खुशियां मनाई गई। सुमन मिश्रा ने कहा पुलिसकर्मियो ने निर्भया कांड के दुष्कर्मियो को गिरफ्तार कर बहादुरी का काम किया वही नीलम शर्मा ने कहा कोर्ट ने दुष्कर्मियो को फांसी की सजा देकर पुण्य कार्य किया हैं, ऐसे ही सभी दुष्कर्मियो को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, सभी दुष्कर्मियो को सबक मिले। इसके पुर्व सुखदेवनगर थाना प्रभारी संजय कुमार एवं पण्डरा थाना प्रभारी शशिरंजन कुमार जी सहित सभी पुलिसकर्मियो के बीच कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क वितरण किया गया, स्त्री रोग विशेषज्ञ ने करोना वायरस से बचने के लिए विस्तृत

रूप से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में थाना परिवार को महापर्व श्री रामनवमी पुजा कि बधाई दी गईं।

कार्यक्रम में मुख्यरूप से क्लब के संस्थापक शिव किशोर शर्मा, संरक्षक नीलम शर्मा, प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ डॉ मृणलिणी सहित शोभा वर्णवाल, मुकेश ठाकुर, संतोष कुमार, लक्ष्मण गोप, रमेश पंडित आदि शामिल थे।

मंगलवारी शोभायात्रा निकाली गयी

रांची : 17मार्च को रामनवमी पूजा समिति, राजेन्द्र चैक, पिस्कामोड़ में पूजा अर्चना के बाद बाजे-गाजे के साथ मंगलवारी शोभायात्रा झाँकी निकाली गई। इस अवसर पर पिस्कामोड़ चौक में महावीरी झण्डा ध्वजारोपण भी किया गया। इस महोत्सव में पिस्का मोड़ श्री विश्वनाथ शिव मंदिर के संस्थापक शैलेश्वर दयाल सिंह, अक्षय पाठक, शिव किशोर शर्मा, अरूण कुमार, पूजारी विक्की तिवारी, आनंद मण्डल, गौतम वर्मा, दुकान्दार संघ सहित काफी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल थे। महोत्सव की समाप्ति महाआरती एवं प्रसाद वितरण के साथ हुई।

राष्ट्रीय एससी/एसटी हब वेंडर विकास कार्यक्रम का आयोजन

संवाददाता

रांची : सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस स्थित 'विचार मंच' में 'राष्ट्रीय एससी/एसटी हब वेंडर विकास कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक (एमएम) ए.के. ठाकुर, महाप्रबंधक (भंडार) एस.पी. नारायण, महाप्रबंधक (उत्खनन) ए.के. झा, महाप्रबंधक (सीएमसी) राजीव सिंह, महाप्रबंधक (नगर प्रशासन) आर.के. श्रीवास्तव, एससी/एसटी हब, राज्य प्रमुख विनोद कुमार, मुख्य प्रबंधक (वाशरी) रमन कुमार के अतिरिक्त बड़ी संख्या में एससी/एसटी उद्यमी एवं सीसीएल के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एसटी/एससी उद्यमियों को उद्योगों में आगे लाने के लिए आयोजित किया गया था। लघु उद्यमियों के सर्वांगींण विकास के लिए सीएमडी गोपाल सिंह के दिशा-निर्देश में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरूआत किया गया। अवसर विशेष पर एससी/एसटी हब, राज्य प्रमुख श्री विनोद कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का निर्देश भी आया है कि एसटी/एससी उद्यमियों को आगे बढ़ाना है, इन्हें प्रेरित कर आवश्यक सुविधाएं देकर सफल उद्यमी बनायें। सभी सार्वजनिक उपक्रमों से यही अपेक्षा है।

अपने संबोधन में महाप्रबंधक (एमएम) श्री ए.के. ठाकुर ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि एससी/एसटी उद्यमियों को आगे बढ़ाया है। सीसीएल प्रबंधन ने भी 5 प्रतिशत आरक्षण गुडस प्रॉक्यूमेंट पर एससी/एसटी उद्यमियों के लिए रखा है। हमारे सीएमडी गोपाल सिंह का भी कहना है कि इन्हें आगे बढ़ाना है और इस हेतु प्रेरित करना है। मैं आप सभी से सुझाव मांगता हूँ, आप सभी आगे आयें और हमारे साथ कार्य करें। इस अवसर पर महाप्रबंधक (उत्खनन) श्री ए.के. झा, महाप्रबंधक (सीएमसी) राजीव सिंह एवं महाप्रबंधक (नगर प्रशासन) श्री आर.के. श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया और वेंडरों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दिये।

इस कार्यक्रम में शामिल उद्यमियों को सीसीएल प्रबंधन द्वारा सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में भी अवगत कराया गया। मंच संचालन श्रीमती मिनाक्षी एवं धन्यवाद ज्ञापन बी.एम. दास ने किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में एमएम विभाग के साथ राष्ट्रीय एससी/एसटी हब जिडको, रांची एवं टिक्की का सक्रिय रूप से योगदान रहा।

कोरोनावायरस और साफ पानी का महत्व

एजेंसियां : जिस वक्त हम सार्स-सीओवी-2 का सामना कर रहे हैं, पानी की उपलब्धता ही इस बात का निर्धारण करेगी कि हम इस लड़ाई को जीत पाते है या नहीं

22 मार्च को विश्व जल दिवस है। नोवेल कोरोनो वायरस बीमारी (कोविड-19) हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है. ऐसे में, यह समझने की जरूरत है कि सब के लिए स्वच्छ और सुलभ तरीके से पानी की उपलब्धता कितना महत्वपूर्ण है।

इस महामारी से बचने का एकमात्र अचूक उपाय यही है कि हम लगातार अपने हाथों को हर बार 20 सेकंड तक धोएं। यानी, साफ पानी रोगों के रोकथाम के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। ऐसे में, नोवेल कोरोनो वायरस जैसे वैश्विक दुश्मन को हराने में पानी की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण निर्धारक होगी।

हममें से अधिकांश इस बात से निश्चिंत हो सकते है कि हम अपने नल से पानी लेते हैं। अगर पानी साफ नहीं है, तो हम बोतलबंद पानी का विकल्प चुन लेते है। लेकिन हम दो चीजें भूल जाते हैं।

पहला, जो पानी हम खरीदते हैं, वह भी सार्वजनिक स्रोतों से ही आता है, यानी ज्यादातर वे भूजल होते है। दूसरा, हम ये सोच कर बोतलबंद पानी खरीदते है कि ये

''सुरक्षित'' है, और पानी को मूत्र के रूप में उत्सर्जित करते हैं। यानी, जितना अधिक पानी हम उपयोग करते हैं, उतना अधिक सीवेज (गन्दा पानी) हम उत्पन्न करते हैं। यदि इस सीवेज का उपचार नहीं होता है, तो यह प्रदूषण और जलजमाव की समस्या पैदा करेगा। यानी, हम एक बार फिर गंदे पानी की ओर लौटते है।

जल संकट एक स्वास्थ्य संकट है। कोरोना वायरस का उदाहरण देखे। 20 सेकंड हाथ धो कर वायरस को मारने की सलाह दी जाती है। इसका अर्थ होगा हर बार हाथ धोने पर लगभग 1.5-2 लीटर पानी खर्च करना। इस तरह, बार-बार हाथ धोने का मतलब होगा कि हमें प्रति व्यक्ति 15-20 लीटर पानी की आवश्यकता है। यानी, पांच सदस्य वाले घर को केवल हाथ धोने के लिए 100 लीटर पानी की आवश्यकता होगी।

यदि आप हाथ को साबुन से धोते वक्त नल बन्द रखते है, तब भी पानी की खपत अधिक होगी। हमारे सामने ये चुनौती है कि भारत समेत उभरती हुई दुनिया के बड़ी जनसंख्या की पानी तक पहुंच नहीं है। फिर वे इस वायरस से कैसे मुक्त होंगे? महामारी हमें सिखाती है कि हम इस श्रृंखला में उतने ही कमजोर है, जितने दुनिया के सबसे कमजोर लोग. यानी, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हर किसी के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य तक पहुंच हो, ताकि कोई भी इस वायरस का वाहक न बन सके। पानी के साथ भी ऐसा ही है। यदि लोगों के पास साफ पानी नहीं है, तो वे बीमारी को फैलने से नहीं रोक पाएंगे।

अच्छी खबर यह है कि हमें पता है कि क्या किया जाना चाहिए। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम वर्षा जल के हर बूंद को सहेजे, स्थानीय जल भंडारण प्रणालियों का निर्माण करें, कम पानी की जरूरत वाली फसलें खाएं और अपशिष्ट जल की हर बूंद को रीसायकल कर इस्तेमाल करें। वर्तमान प्रणाली इतनी महंगी है कि साफ पानी कुछ घरों तक ही पहुंचाया जा सकता है। अधिक दूर से पानी लाने के लिए जितनी लंबी पाइप लाइन होगी, आपूर्ति की लागत उतनी ही अधिक होगी। हमारे शहरों में बड़ी संख्या में लोगों को पाइप से जलापूर्ति की सुविधा नहीं मिलती है। वे टैंकरों से पानी लेते हैं या पीने के पानी और अन्य जरूरतों के लिए गंदे और अविश्वसनीय जल स्रोतों पर निर्भर करते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। पानी की आपूर्ति की लागत जितनी अधिक होगी, पानी को सीवेज से वापस ला कर उसका उपचार करने पर खर्च कम होता जाएगा। ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमें आपूर्ति प्रणाली को फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है। हमें पानी के उपयोग को कम करके मांग को फिर से डिजाइन करना होगा, ताकि हम पानी की बर्बादी कम कर सकें। हमें सीवेज प्रबंधन को फिर से डिजाइन करने की जरूरत है।

कुल मिला कर बात ये है कि साफ पानी सभी के लिए सस्ती और सुलभ होनी चाहिए वर्ना यह किसी के लिए भी दीर्घकालिक तौर पर उपलब्ध नहीं रहेगी।

फोटो न्यूज

22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन यात्रियों की भीड़ और शोरगुल से गुलजार रहने वाला रांची रेलवे स्टेशन बिल्कुल ही खाली रहा।

बेमौसम बारिश ने किसानों को आत्महत्या के कगार पर पहुंचाया

पूरे उत्तर भारत में हाल में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि में करोड़ों के मूल्य की फसल बरबाद हो गई. नुकसान के सदमे से कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है.पिछले सप्ताह पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में सिर्फ बेमौसम बारिश ही नहीं हुई बल्कि ओले भी गिरे. जहां आम नागरिकों के लिए यह मौसम की असामान्य घटना थी, तो वहीं इन सभी राज्यों में महीनों से अपनी-अपनी फसल पर मेहनत कर रहे किसानों के लिए यह एक भारी आपदा थी।उत्तर भारत में सर्दियों में रबी का कृषि मौसम होता है जिसमें गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर दाल इत्यादि जैसी फसलें बोई जाती हैं और वसंत ऋतू में इनकी कटाई होती है. पिछले सप्ताह जब बारिश के साथ ओले गिरे तब इन सभी राज्यों में फसल या तो कटाई के लिए तैयार खड़ी थी या काट कर मंडी में ले जाने के लिए. दोनों ही सूरतों में फसल असुरक्षित थी और हुआ वही जिसका किसानों को डर था. इतनी फसल बर्बाद हो गई जिसका मूल्य करोड़ों में जाएगा। एक अनुमान के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 255 करोड़ रुपये मूल्य की फसल बर्बाद हो गई. ये बर्बादी प्रदेश के कम से कम 35 जिलों में देखी गई और इस से प्रदेश के लगभग 6.5 लाख किसान प्रभावित हुए. जिला प्रशासन का कहना है कि जिलों की तरफ से नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है और अभी तक किसानों की फौरी मदद के लिए जिलों को 66 करोड़ रुपये की धनराशि दे भी दी गई है. पर यह राशि पर्याप्त नहीं है. देखना होगा कि फसल बीमा योजना इन हालत में किसानों के कितना काम आती है.

अंतरराष्ट्रीय जल दिवस की सार्थकता हमारे पहनावे से भी होगी

जीन्स टी - शर्ट का उत्पादन में हजारों लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाना

दरअसल हर साल जल दिवस के लिए एक थीम तय की जाती है इस बार की थीम है "जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव", यानी लोगों को यह जागरूक करना है कि जलवायु परिवर्तन का किस तरह से जल संसाधनों पर प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई ? तो सबसे पहले शुरुआत करने का फ़ैसला संयुक्त राष्ट्र ने 22 मार्च 1993 को लिया था ताकि सभी के लिए स्वक्ष और सुरक्षित जल मुहैया कराया जा सके। दुनियाभर को छोड़कर सिर्फ हिंदुस्तान की स्थिति को देखने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगाएं तो हमारा गला सूखने लगेगा। यदि दिवसों की बौछार में जल को शामिल करें तो अपने भारत में भी 22 मार्च के अलावे 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं, तथा 1 दिन और हम जल संसाधन दिवस को मनाने में बिताते हैं । यह अलग-अलग तरह के दिनों में जल पर कार्यक्रम करके हम इतिश्री कर देते हैं , इस तरह का भाषण इसलिए है क्योंकि हम इसी के उलट पूरा अपना दिनचर्या में पानी की गंभीरता को ना लेकर लापरवाह हो जाते हैं। अगर बात लोगों के पहनावे को लेकर करें तो इसमें जींस और टीशर्ट आज के हर पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण पहनावे के रूप में अपनाया जाने लगा है। अब आपके मन मस्तिष्क में सवाल कौंध रहा होगा कि जल और पहनावे से क्या तात्पर्य है? तो जवाब में सीधे तौर पर तो नहीं बल्कि जो हम बहुत उम्दा किस्म के जींस टीशर्ट को बहुत शौक से पहनते हैं उसका उत्पादन करने में पानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है

क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक जींस और टीशर्ट बनने में कितना लीटर पानी खर्च होता होगा?

तो उत्तर जानने के लिए अपनी फेवरेट जींस और टी- शर्ट लिवाइस ,जॉर्डेएक, रेंगलर इत्यादि जो भी हो उसको उठाइए और उसको बनाने में तकरीबन एक व्यक्ति यदि 1 दिन में 5 लीटर पानी पी रहा है तो एक जीन्स और टी शर्ट बनाने की प्रक्रिया में उतना पानी खर्च होगा जितना वह 7 साल में रोजाना पिएगा।औसतन 12900 लीटर पानी का खर्च होता है। इसके अलावे कपड़े को धोने में बर्बाद होने वाला पानी अलग है।

जींस बनाने में पानी खर्च होने का सबसे बड़ा कारण कॉटन की खेती से जुड़ा है

1 किलोग्राम कॉटन की खेती में औसतन 10,000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। वही यदि इरिगेशन मेथड से खेती की जाए तो 2000 लीटर पानी का कम खर्च होता है, अर्थात 8000 लीटर । दुनियाभर में कॉटन की खेती के मामले में भारत शीर्ष देशों में आता है तथा भारत में पानी का जलस्तर लगातार गिरता भी जा रहा है इसपर विचार करने की जरूरत भी है ।

अब अगर कुछ के मन में यह विचार कौंधेगा की पॉलिस्टर का भी जींस प्रयोग कर सकते हैं विकल्प के तौर पर, तो इस पर वही वाली बात हो गई की आप इस कान को पकड़िए या फिर उस कान को बात बराबर ही है। क्योंकि पॉलिस्टर को बनाने में 2 से 3 गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से खतरनाक है । तथा यह प्लास्टिक का रूप भी धारण करता है जो घातक है।

विकासशील देशों में जींस के उत्पादन को लेकर जल स्रोतों पर क्या प्रभाव पड़ा

ज्यादातर कपड़े बांग्लादेश, तुर्की, कजाकिस्तान, कंबोडिया जैसे देशों में बनते हैं। इस मामले में सबसे सटीक उदाहरण कजाकिस्तान की अराल सी लेक से है। आज यह तकरीबन तकरीबन सूख चुकी है, यही लेक 50 साल पहले दुनिया की 4 सबसे बड़ी झीलों में शामिल थी । इसका सबसे बड़ा कारण कॉटन की खेती के लिए पानी का अत्यधिक दोहन करना है।

सामंजस्य बैठाकर इस्तेमाल करने की आवश्यकता :इसका मतलब यह नहीं है के लोग जींस पैंट पहनना बंद कर दे लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि 1 साल में जो पांच छह जोड़ियां कपड़े खरीदते हैं वह आप कम कर सकते हैं। अर्थात एक कपड़े को लंबे अवधि तक पहन सकते हैं। आपको पुराने कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ रही है तो कई ऐसे संस्थाएं हैं जिन्हें आप दान कर सकते हैं, इससे वह लैंडफिल साइट्स में जाने से बच जाएंगे। आप स्मार्ट लॉन्ड्री मैनेजर की तरह बनिए, जिसमें आप एक बार में अधिक कपड़ों को साफ कर सके। **शशिभूषण**

नौ फीट कम हुआ है धुर्वा डैम का जलस्तर

राजेश कुमार

●पेयजल मंत्री की रिपोर्ट में खुलासा

●दूसरे स्रोतों से पानी लाने पर जोर

रांची : झारखंड की राजधानी रांची के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने वाले एक धुर्वा डैम का जलस्तर घट रहा है। तीन सालों में इसके जलस्तर में नौ फीट की कमी आई है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। उन्होंने डैम में दूसरे स्रोत से पानी लाने की वकालत की है। इस बाबत सचिव को कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।

डैम का किया था निरीक्षण

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने 24 फरवरी, 2020 को धुर्वा डैम के निरीक्षण किया था। इस क्रम में मिली जानकारी से विभागीय सचिव को अवगत कराया। विभागीय मंत्री ने कहा कि धुर्वा डैम का जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है। यह काफी चिंता का विषय है। इसके विपरीत रूक्का डैम और अन्य जलाशयों की स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि धुर्वा डैम के कैचमेंट एरिया निकट के प्रखंड कर्रा, बेड़ो एवं लापुंग का क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में बारिश कम होती है तो निश्चित रूप से धुर्वा डैम का जलस्तर काफी नीचे चला जाता है।

आने वाले दिनों में डैम महत्वपूर्ण

मंत्री ने कहा कि मार्च 2017 में डैम का जलस्तर 2183 फीट था, जो आज 3 वर्षों के बाद 2174 फीट हो गया है। जिस तरह से रांची शहर का विस्तार हो रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में धुर्वा डैम बहुत ही महत्वपूर्ण जलस्रोत साबित होगा। स्मार्ट सिटी, नई विधानसभा, उच्च न्यायालय और आवासीय कॉलोनी सभी धुर्वा डैम के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हो रहे हैं। इन क्षेत्रों के लोग पेयजल के लिए पूर्ण रूप से धुर्वा डैम पर ही निर्भर रहेंगे।

यहां से पानी लाने की वकालत

मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इस परिपेक्ष्य में अगले पचास सालों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्य योजना बनानी होगी। लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए धुर्वा डैम के जलस्तर और जलस्रोतों को बढ़ाना होगा। गुमला जिले के सिसई प्रखंड अंतर्गत नागफेनी से दक्षिणी कोयल नदी का प्रवाह है। यह बारहमासी नदी है। इसमें सालों भर पानी रहता है। यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अगर इस नदी के पानी को धुर्वा डैम में लाने की योजना बनाई जाती है, तो आने वाले दिनों में धुर्वा डैम का जलस्तर हमेशा बना रहेगा। रांची शहर की एक बड़ी आबादी को निरंतर पानी मिलता रहेगा। इसके अलावे भी अन्य निकटतम जलस्रोत, जिससे धुर्वा डैम को पानी मिल सके उसकी भी संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता पर बल दिया है।

कार्य योजना तैयार करने का निर्देश

इस संबंध में विभागीय मंत्री ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव को कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सचिव से कहा कि वे अपने अभियंताओं और जल संसाधन विभाग के सचिव एवं अभियंता के साथ बैठक कर जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करें, ताकि इस कार्य योजना को अगले वित्तीय वर्ष में अमलीजामा पहनाया जा सके।

मिश्रित खेती का इतिहास हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है

सदियों से कृषि और पशुपालन की प्रथा चली आ रही है और उसके महत्व से भी सभी परिचित है। खेती के साथ पशुपालन करना एक-दूसरे से जुड़ा हुआ था क्योंकि खेती के लिये ऊर्जा (पावर) पशुओं के द्वारा ही प्राप्त होता था साथ में गाय/भैंस को खिलाने के लिये पर्याप्त भूसा भी खेती से ही मिलता था। इस तरह खेती और पशुपालन एक-दूसरे के लिये परिहाय या यूं कहें कि पूरक ही थे। पशुओं से प्राप्त गोबर खाद का उपयोग खेती के लिये उपयोगी और आवश्यक होता था। सीमित आबादी, लम्बी-चौड़ी जोत के चलते दशकों यह चक्र चलता रहा परंतु धीरे-धीरे जनसंख्या का विस्तार होता गया और कुटुम्ब/ परिवार बढ़ते गये बंटवारे की जरूरत सामने आने लगी और जरूरत के अनुरूप अनाज इस सीमित कृषि क्षेत्र से पाना असंभव होने लगा और इस चुनौती का सामना करने के विकल्प की खोज शुरू हो गई। कहावत है अविष्कार की तह में आवश्यकता ही रहती है। कम क्षेत्र से अधिक अन्न की प्राप्ति के लिये अनुसंधान के द्वारा विभिन्न फसलों की बोनी किस्मों को पैदा किया गया जिनकी खुराक अधिक थी केवल धरती में उपलब्ध पोषक तत्वों के भरोसे उनकी क्षमता के अनुसार पैदावार सम्भव नहीं थी इस कारण रसायनिक उर्वरकों के उपयोग का युग शुरू हुआ रसायनिक उर्वरकों की मांग भरपूर पानी होती है इस कारण जतन किये गये और जगह-जगह जहां जैसा सम्भव था छोटे, मध्यम, बड़े बांध बनाकर वर्षा के जल का संग्रहण किया गया और खेतों में लहलहाती फसल को काटने/गहाने के लिये मशीनों के उपयोग का युग भी इस प्रगति में जुड़ गया बस इसी मशीनीकरण/नवीनीकरण के कारण खेती से पशुओं के अटूट रिश्ते में दरार पडने लगी और धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्र में भी खेती के साथ पशुपालन के व्यवसाय को एक बड़ा धक्का लगा। दशकों तक अंधाधुंध उर्वरकों के उपयोग के साथ अनियंत्रित जल के उपयोग करने से भूमि के स्वास्थ्य पर असर पडने लगा और हमारी आधुनिक खेती के दुष्परिणाम सामने आने लगे और एक बार फिर से सभी का ध्यान खेती के पुराने तरीकों पर वापस जाने पर बाध्य हो गया ।

नई तकनीक से कम नमक खायेंगे हम और स्वाद भी रहेगा बरकरार

एजेंसियां: वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक खोजी है, जिससे खाने में नमक की मात्रा को 50 फीसदी तक कम किया जा सकता है और स्वाद भी बरकरार रहेगा। बहुत अधिक नमक खाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता हैं और फास्ट फूड में आम तौर पर स्वाद और इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अधिक नमक का उपयोग किया जाता है।इसी को लेकर अमेरिका स्थित वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी ने नई प्रासेसिंग तकनीक ईजाद की है, जिसे माइक्रोवेव असिस्टेड थर्मल स्टेरलजेशन (एमएटीएस) कहा जाता है। इसकी मदद से भोजन में सुरक्षा और स्वाद को बनाए रखते हुए नमक (सोडियम) को कम करना संभव है।

यह अध्ययन जर्नल ऑफ फूड साइंस में प्रकाशित हुआ है। डब्ल्यूएसयू के शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में पाया कि एमएटीएस प्रासेसिंग से भोजन में किसी भी रोगाणुओं को मारने के लिए माइक्रोवेव तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, इससे भोजन के स्वाद को बरकरार रखा जा सकता है। जबकि खाद्य प्रसंस्करण (प्रोसेस्ड फूड्स) को सुरक्षित रखने की मौजूदा विधि, जिसे रिटॉर्ट कहा जाता है, भोजन के स्वाद को कम कर देती है।अध्ययन में मैश किए हुए आलू को मौजूदा विधि रिटॉर्ट और नई तकनीक एमएटीएस के उपयोग से अलग-अलग पकाया गया। दोनो विधियों से बने भोजन को चखने के लिए एक खास पैनल था। नमक, काली मिर्च और लहसुन जैसे अन्य सामग्रियों की तीव्रता को मापने के लिए डब्ल्यूएसयू द्वारा निर्मित ई-जीभ (ई-टंग) का उपयोग किया गया।प्रमुख शोधकर्ता कैरोलिन रॉस ने कहा कि एमएटीएस विधि में काली मिर्च की तीव्रता ताजे आलू में समान थी, जबकि रिटॉर्ट प्रसंस्करण विधि में इसमें कमी पाई गई। रिटॉर्ट की गरम करने की प्रक्रिया और ठंडा होने में अधिक समय लगता है, जो भोजन के टेक्स्चर और स्वाद को बदल देता है।एमएटीएस में यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, इसलिए भोजन पर उतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। डब्लूएसयू के साशा बार्नेट, श्याम सबलानी और जुमिंग टैंग सहित शोधकर्ताओं ने पाया कि एमएटीएस द्वारा तैयार मैश किए हुए आलू में नमक की मात्रा को 50 फीसदी तक कम किया जा सकता है।डब्ल्यूएसयू के स्कूल ऑफ फूड साइंस में प्रोफेसर रॉस ने कहा कि चखने के बाद वे बता सकते हैं कि यह उतना नमकीन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें यह पसंद आया क्योंकि इसमें अन्य सामग्रियों के स्वाद की मात्रा अधिक थी। खास तौर पर, यदि आप हर्ब्स के स्वाद को बढ़ा देते हैं, तो भोजन बिना अधिक नमक के भी नमकीन लगता है।रॉस ने कहा कि एमएटीएस तकनीक अभी भी अपेक्षाकृत नई है, लेकिन यह प्रसंस्कृत खाद्य (प्रोसेस्ड फूड्स) पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले नमक को कम करने में मदद कर सकती है।

शोधकर्ता ने कहा, हमें एक ऐसा उत्पाद बनाना है, जिसे लोग खाना चाहते हैं। लोग तैयार भोजन खाना पसंद करते है, लेकिन इसमें सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरुरी हैं। इसलिए यदि हम उन खाद्य पदार्थों से नमक को कम कर देते हैं, और स्वाद भी बरकरार रहता है, तो यह बहुत फायदेमंद हो सकता है।

पाइलकोट झारखण्ड और देश कर एतिहासिक महत्व वाला ठांव हय

बलदेव शर्मा

गतांक कर आगे.....

एखन तक अब हमरे झारखण्ड कर आध्यात्मिक व एतिहासिक महत्व वाला ठांव पाइलकोट आउर ऋष्यमुक पर्वत कर बारे में कुछ कुछ जाइन गेली। ऐहे लागिनी अब तनी हम राउरीन के इहां कर नागवंशी राजा जे आपन किला आउर महल नी बनाय के पहाड़ तरे रहेक कर कुछ रहस्य जे पुराना बुढ़ा बुजुर्ग मन कहत रहयं । उ मनकर मुंह से सुनल बात के राउरे मनकर बीच राखत्थी।

जेखन अंग्रेज मनकर शासन रहे। सेखन अंग्रेज मनकर बाद शासन के नीचे स्तर तक पहुंचायक कर पावर जमींदार मनके देवल जाय रहे। इ इलाका में एगो बड़ा जबरजस जमींदार अरमई स्टेट कर हरिशंकर लाल रहयं। कहल जायला इ तीन सौ पैंसठ गांव कर मालिक रहंय। पाइलकोट गांव भी इनकरे जमींदारी में आवत रहे। से लागिन हरिशंकर लाल रातू महराज ठीन आपने के राजा घोषित करेक ले दावा भी कइर रहयं। मुदा कोनो कारण से रातू गढ़ कर महाराजा उनके राजा कर उपाधि देवेक से मना कईर देलैं। तब जमींदार हरिशंकर लाल नाराज होई गेलयं आउर कहलयं कि पाइलकोट कर राजा लाल कंदर्प नाथ शाहदेव तो हमर रैयत हेकयं। काहे कि हायर जमींदारी गांव कर पानी पियंना। इ बात राजा साहेब कर कान में पहुंचलक तो राजा साहेब गांव कर

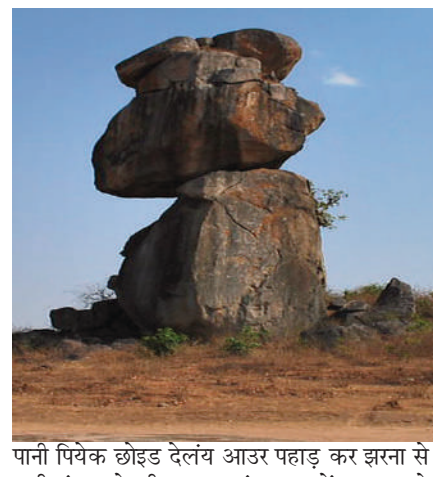

पानी पियेक छोइड देलंय आउर पहाड़ कर झरना से पानी मंगाया के पीएक लागलंय। बाद में पहाड़ उपरे कर झरना के लकड़ी कर डोंगा (नली) बनाय के पानी घर भीतरे भीतरालयं। सेहेखन से पाइलकोट कर राजा इ डोंगी कर पानी पीयथयं। अब डोंगी हटाय के लोहा कर पाइप लगाय देहंय। लेकिन कहल जाएला जमींदार हरिशंकर लाल एतना से भी नइ मानलंय। काहे कि उनकर राजा बनेक कर सपना के तोरल जाय रहे। राजा के अपने जमींदारी कर अंडर देखाएक रहे। कहलंय कि पहाड़ जंगल भी हमर जमींदारी कर अंडर में आवेला। जमींदार मनकर से बेरा वैसन चलतेहें रहे। क्रमशः...

(इ कहनी कर हम एखन तक कोनो लिखल प्रमाण नी पायही। बुजुर्ग मनकर कहेक पर आधारित हय)।

अशुद्ध जल से हाथ धोना न धोना बराबर

एजेंसियां : विश्व में 190 करोड़ लोगों के पास उपयोग केलिए शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। नावेल कोरोनावायरस (कोविड-19) से जूझने के मामले में भारत की वाहवाही हो रही है। हाथ धुलाई को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और उसमें बड़ी हस्तियों को भी शामिल करने जैसे प्रयासों की काफी चर्चा हो रही है। इस बीच एक चिंता सामने आ रही है कि माध्यम आय वर्ग वाले देश जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और एशिया के साथ भारत में साफ पानी की सुविधा कम लोगों को ही उपलब्ध है। विश्वभर में निम्न माध्यम आय वाले देश के 180 करोड़ लोग बेहद प्रदूषित पानी का उपयोग करते हैं। इन आंकड़ों का खुलासा ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड इंटरनेशनल हेल्थ नामक पत्रिका में 2014 में छपे एक शोध से हुआ। इन देशों में लोग पानी में मौजूद सूक्ष्म प्रदूषण से ग्रस्त हैं और दक्षिणी विश्व में गंभीर किस्म का प्रदूषण पानी में पाया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टकहती है कि पूरे विश्व में तकरीबन 190 करोड़ आबादी द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल पीने, साफ सफाई और दूसरे कामों के लायक ही नहीं होता, और इस पानी का स्त्रोत मुख्यतः भूजल है।भारत में 6,50,000 गांवों में सफलतापूर्वक 1.64 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। सेंटर फ़ॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए शोध के अनुसार, मल उपचार की तकनीक सभी शौचालयों के लिए सुरक्षित नहीं है। अफ्रीकन देशों जिनमें नाइजीरिया, यूगांडा और केन्या शामिल हैं, में ऐसी ही स्थिति देखी का सकती है। सारे देशों के पास साफ सफाई के दुरुस्त इंतजाम नहीं हैं। खुले में शौच और शौचालय में मल उपचार की अच्छी तकनीक न होने की वजह से बिना उपचारित या आधा-अधूरा उपचारित मल पानी के स्त्रोतों में जा मिलता है।

इससे भूजल और मिट्टी दोनों प्रदूषित होती है। इन देशों में ग्रामीण और कस्बाई आबादी भूजल या खुले जल स्त्रोतों पर निर्भर है जहां स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है।

जलजनित रोगों में डायरिया सबसे अधिक जान लेने वाला रोग बना हुआ है जिसकी वजह से 60 प्रतिशत मृत्यु जो रही है। यह आंकड़ा पूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने लोक सभा में एक सवाल के जवाब में वर्ष 2018 में पेश किया था।

हैजा, टाइफाइड और वायरल हैपेटाइटिस पानी से होने वाले अन्य रोग हैं जिससे अक्सर ग्रामीण आबादी प्रभावित होती है। पानी से होने वाली बीमारियों से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण डायरिया है।केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा जारी वार्षिक प्रकाशन 2019 के नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के अनुसार, 2017 में 1,362 और 2018 में 1,450 लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो गई थी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अतिरिक्त निदेशक दीपांकर साहा के अनुसार, भारत के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में हाथ धोने का मतलब दूषित पानी का उपयोग करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में भूजल में प्रवेश करने वाले जैविक प्रदूषक तत्व आज के समय में एक प्रमुख चिंता का विषय है।हालांकि, यदि हाथ धोने में साबुन का इस्तेमाल हो रहा है तो यह पानी में मौजूद जीवाणु को खत्म करने में सक्षम है। साफ पानी को लोगों तक पहुंचा कर कोविड-19 जैसे बीमारियों से पुख्ता तरीके से लड़ा जा सकता है।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।